भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
28.07.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1493 का उत्तर

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1493. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की गति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में गैर-उपनगरीय स्टेशनों सहित रेलवे स्टेशनों के सभी ग्रेडों पर उच्च स्तरीय प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई हैं; और

(घ) इन सभी स्टेशनों का आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के संबंध में 28.07.2021 को लोक सभा में श्रीमती रेखा अरुण वर्मा के अतारांकित प्रश्न सं. 1493 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रेल में स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण/सौंदर्यीकरण एक सतत और चालू प्रक्रिया है। इस समय, रेलवे स्टेशनों को 'आदर्श' स्टेशन योजना के तहत उन्नत/आधुनिक बनाया जाता है, जो स्टेशनों पर बेहतर संवर्धित यात्री सुविधाएं मुहैया कराने की चिन्हित आवश्यकता पर आधारित है। उत्तर प्रदेश राज्य में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित करने के लिए 152 स्टेशनों की पहचान की गई है। इनमें से, इस योजना के तहत 131 स्टेशन विकसित किए जा चुके हैं। शेष 21 स्टेशनों को वित्त वर्ष 2021-22 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जाने का लक्ष्य है।

स्टेशन की कोटि के अनुसार 'आदर्श' स्टेशन योजना के तहत विभिन्न यात्री सुविधाएं अर्थात् स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार, विश्रामालय, प्रतीक्षालय (स्नान की सुविधाओं के साथ), महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षालय, कंप्यूटर आधारित जन उद्घोषणा प्रणाली, परिपथन क्षेत्र का भू-निर्माण, संकेतक, पे एंड यूज़ शौचालय, वाटर कूलर, उच्च सतह वाले प्लेटफार्म, ऊपरी पैदल पुल, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टेशन के प्रवेश द्वार पर रैंप आदि मुहैया कराई जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों, मरीजों के लिए सुगम आवागमन की सुविधा देने के लिए और प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर सुगम पहुंच के लिए तथा सुगम आवागमन हेतु, न्यूनतम प्रतिदिन 25,000 तथा इससे अधिक पैदल यात्रियों वाले रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर मुहैया कराए जाते हैं।

इसके अलावा, भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों के लिए 'सुगम्य भारत अभियान' के भाग के रूप में, रेलवे स्टेशनों पर लिफ्टें मुहैया कराई जाती हैं जो विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकता तथा लिफ्टों के प्रावधान के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। अब तक (30.06.2021 की स्थिति के अनुसार), उत्तर प्रदेश राज्य में गैर-उपनगरीय स्टेशनों सहित 28 स्टेशनों पर 83 एस्केलेटर और 27 स्टेशनों पर 70 लिफ्टें मुहैया कराई गई हैं।

इसके अतिरिक्त, सॉफ्ट अपग्रेडेशन के तहत विकास करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 68 स्टेशनों को चुना गया है। इनमें से उत्तर प्रदेश में 07 स्टेशनों अर्थात् पं. दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज, झांसी, मथुरा, वाराणसी सिटी, इज्जतनगर और गोरखपुर को काफी हद तक उन्नत कर दिया गया है।

रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/उन्नयन/संवर्धन के कार्य के लिए आबंटन/व्यय को आमतौर पर योजना शीर्ष 'यात्री सुविधाएं' के तहत वित्त पोषित किया जाता है। 17 क्षेत्रीय रेलवे और 8 उत्पादन कारखाने रेलवे के लेखांकन और बजट की इकाइयां हैं। इसलिए, आबंटित/व्यय की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 201819, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किया गया व्यय क्रमश: 1585.88 करोड़ रु., 1903.11 करोड़ रु. और 2582.90 करोड़ रु. है।

*****